

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक
 जिला....., सं०....., सन् १९.....
 केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	<p style="text-align: center;">न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील वाद संख्या 51/2012</p> <p style="text-align: center;">रामदेव यादव एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम शिवनन्दन यादव एवं अन्य — रेष्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण</p> <p style="text-align: center;">—:आदेश:—</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, त्रिवेणीगंज के आदेश दिनांक: 17.01.2012 ई० अंदर वाद संख्या- 01/11-12 के विरुद्ध खिलाफ रेष्पाण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।</p> <p>वाद पुकारा गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित उभय पक्षों के सभी कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद में विवादी भूमि अन्दर मौजा- पिलुआहा खाता- 143 ग एवं 01 खेसरा-1715 एवं 1711 रकबा 0.4.0 डीसमल वो 0.4.0 डीसमल कुल 0.8.0 डीसमल में से 4 कट्ठा प्रश्नगत भूमि है।</p> <p>अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि सरयुग यादव के पिता गेना मंडल के द्वारा अर्जित थी। जिन्होंने विवादित प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 को निबंधित बिक्री दस्तावेज के माध्यम से बिक्री कर दी। तदनुसार क्रेता का नाम बिहार सरकार सिरिस्ता में दर्ज हुआ एवं जिसका जमाबंदी 1124 चलती है। कय की गयी भूमि कय के उपरांत क्रेता के दखल में आयी। रेष्पाण्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उनके पिता सरयुग यादव के जीवित रहते हुए ही अवैधानिक रूप से अपनी पत्नी के नामे निबंधित दान पत्र तामिल किया।</p> <p>अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपने पिता सरयुग यादव के जीवित रहते हुए ही रेष्पाण्डेन्ट संख्या 1 को निबंधित दान पत्र अपनी पत्नी अथवा अन्य के नामे तामिल करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।</p> <p>विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि</p>	

के वास्तविक रैखत गेना यादव के मृत्यु के उपरांत उनके चार पुत्र कमशः सरयुग यादव, फूनी यादव, स्वरूप यादव एवं नेती यादव अपने दादा द्वारा छोड़ी गयी जायदाद के उत्तराधिकारी हुए। सरयुग यादव को विवादित प्रश्नगत भूमि कुल 08.19 धूर भूमि में से एक चौथाई प्राप्त हुआ वो वही उसका वास्तविक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि पत्नी सहित किसी व्यक्ति को दान में देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित प्रश्नगत भूमि का बँटवारा करना निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि मौजाः पिलुआहा के खाता नं० 143 खेसरा नं० 1715 रकबा 0.4.0 जमीन के अलावा दिगर खाता खेसरा वो रकबा की जमीन प्रार्थी प्रतिवादी नं०-1 के दादा वो प्रतिवादी संख्या -2 के ददिया ससुर के नाम से बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी कायम है। गेना यादव अपने पीछे चार पुत्र कमशः फनी यादव, नेती यादव, सरयुग यादव, स्वरूप यादव को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि उक्त वर्णित गेना यादव (मंडल) के पुत्र नेती यादव निःसन्तान फौत कर गए तब जितनी चल वो अचल सम्पत्ति गेना यादव की रही वह चार भागों अर्थात् फनी यादव, नेती यादव, सरयुग यादव, स्वरूप यादव के हिस्से में बँट गई। हिस्सानुसार चारों फरीकें हकदार वो दखलकार चला आ रहा है। प्रश्नगत उक्त वर्णित खेसरा नं० 1711 का कुल रकबा 02.0.02 धूर है वो खेसरा नं० -1715 का कुल रकबा 1.11.07 धूर है। इस खेसरा में आठ कट्टा जमीन सरयुग यादव के पुत्र शिवनन्दन यादव, राम देव को अन्य फरिक्केन फनी यादव, नेती यादव स्वरूप यादव से हिस्सा में मिला। रेस्पोंडेन्ट संख्या -1 के पिता अपीलार्थी संख्या -1 को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त वर्णित खेसराओं के अतिरिक्त दिगर खेसराओं की जमीन दफे व दफे बेचकर रुपया देने लगा तब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 खेसरा संख्या 1711, 1715 में 2-2 कट्टा एवं अन्य खेसराओं को मिलाकर 15 कट्टा जमीन अपनी पत्नी के नाम दिनांक 16.12.93 को दान पत्र केवाला लिख दिया वो केवाला की तिथि से रेस्पोंडेन्ट संख्या -2 हकदार वो दखल घली आई। विधिवत अपने केवाला का दाखिल खारीज होकर जमाबन्दी नं०-1511 कायम किया गया वो मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया।

रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्णित खेसरा नं० 1715, 1711 कुल रकबा आठ कट्टा जमीन अपीलार्थी संख्या 1 दिनांक 17.12.93 को अपने पिता सरयुग यादव से अवैध तरीके से अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 जो 1993 में नाबालिग थे उसके नाम से केवाला करवा लिया वो वर्ष 2010 में जमीन पर गलत दावा करने लगा तब गाँव में सरपंच की मध्यस्तता में एक पंचायत हुआ। पंचायत में दिनांक 29.12.2010 को फैसला हुआ कि दोनों दस्तावेज अवैध हैं। दोनों भाई वर्णित खेसराओं के आधा-2 रकबा 4-4 कट्टा के हकदार हैं।

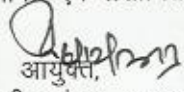
रेस्पोंडेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि जमीन को पुनः कब्जा करने के लिए अपीलार्थी बलवा तकरार करने लगा तब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के लिखित आवेदन पर माननीय एस० डी० एम० साहब त्रिवेणीगंज के द्वारा उपर वर्णित खाता खेसरा की जमीन रकबा 4.9.4 कट्टा पर दफा 144 दं० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी त्रिवेणीगंज के द्वारा दिनांक 24.09.11 को अपने आदेश में खेसरा नं० 1711, 1715 की जमीन के रकबा 4-4 कट्टा पर नियम रिक्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिभिजन दाखिल नहीं किया गया। दखल कब्जा में व्यवधान वो कानूनी रूप से जमीन को माप कर दखल दिलाने हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के द्वारा एक विविध वाद संख्या 01 /2011-12 विद्वान सक्षम प्राधिकार -सह -भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या -2 के द्वारा वादी के रूप में हस्तक्षेपक बना क्योंकि दान पत्र केवाला ज्ञानी देवी के नाम शामिल किया था जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय त्रिवेणीगंज के के द्वारा ग्रहण किया गया वो दिनांक 17.01.12 को 8 कट्टा जमीन में से

4 कट्टा जमीन पर दखल दिलाने का आदेश दिया गया जो न्यायसंगत है ।

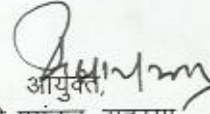
उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी शिवनन्दन यादव द्वारा प्रश्नगत भूमि अपनी पत्नी के नाम से दानपत्र दे दिया गया, लेकिन यह भूमि गेना मंडल के द्वारा अर्जित की गई थी एवं वारिसान होने के नाते सरयुग यादव इसके दावेदार हुए एवं सरयुग यादव के जीवित रहते हुए उनके पुत्र द्वारा भूमि का हस्तान्तरण से विवाद है।

अतः ऐसी परिस्थिति में यह उचित है कि बटवारे के फलस्वरूप दखल कब्जा एवं बिक्री तथा नामान्तरण की जमीन की छानबीन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा इस मामले का गहन छानबीन नहीं की गई है। अतः अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2012 को निरस्त किया जाता है एवं इस मामले को पुनः प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि स्वयं स्थल निरीक्षण कर एवं मामले को सुनकर मामला का निष्पादन दो माह के अन्दर करें। इस प्रकार वाद निस्तार किया जाता है।

लेखापित्त एवं संशोधित।


आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा


आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा